ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-4* May- 2021
Innovation The Research Concept

21 वी शताब्दी में भारत – अमेरिकी संबंध
Indo-us Relations in 21st Century

Paper Submission: 03/05/2021, Date of Acceptance: 15/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021

महेन्द्र कुमार पुरोहित
वरिष्ठ व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय आचार्य (पी.जी.)
संस्कृत महाविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

विश्व मे बदलते भू–आर्थिक व भू–राजनीति के दौर में भारत–अमेरिकी सम्बन्ध नए आयाम में स्थापित हो रहे हैं। वैश्विक उदारीकरण व बाजार व्यवस्था नीति से अमेरिकी हितों की दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ता जा रहा हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक हितो को ध्यान में रखते हुए दोनों देश सामरिक व रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ कर रहे हैं। वैश्विक व क्षेत्रीय सुरक्षा व शांति के लिए दोनों देश सहयोगी बने हुए हैं। लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों, मानवीय हितों, समृद्धि व सुरक्षा की दृष्टि से महान राष्ट्रों के बीच सहयोग व साझेदारी वैश्विक मांग हैं।

In the era of changing geo-economic and geo-political in the world, Indo-US relations are being established in a new dimension. The importance of India is increasing due to global liberalization and market system policy. Keeping in mind the national and strategic interests of India, both the countries are strengthening the strategic and strategic partnership. Both countries remain allies for global and regional security and peace. Cooperation and partnership between great nations in terms of democratic values, human interests, prosperity and security is a global demand.

मुख्य शब्द : भारत, अमेरिका, आर्थिक, लोकतंत्र, रणनीतिक साझेदारी, भू–राजनीतिक। India, US, Economic, Democracy, Strategic Partnership, Geopolitical.

प्रस्तावना

शीत युद्ध के दौर में भारत – अमेरिकी संबंधों में अलगाव ही रहा था। पंडित नेहरू व श्रीमती इंदिरा गांधी का समाजवाद की ओर झुकाव उसकी सोवियत संघ के साथ गहरा के संबंधों का कारण रहा है। इस दौर में अमेरिका भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का भी आलोचक रहा। 1990–91 के पश्चात् बदले वैश्विक परिवेश में भारत – अमेरिकी संबंधों को नई ऊर्जा मिली क्लिंटन प्रशासन के आखिर वर्षों से लेकर वर्तमान तक भारत अमेरिकी संबंध दृढता प्राप्त कर चुके हैं, हालांकि कई मुद्दों पर आज भी दोनों देशों के बीच मतभेद उभरते रहते हैं। विगत दो दशकों में दोनों देशों में सत्ता परिवर्तन के बावजूद साझेदारी व संबंधों में परिपक्वता व गतिशीलता रही है, तथा भविष्य भी इसी उम्मीद पर टिका है।

1991 में भारत में उदारीकरण नीति अपनाने के पश्चात आर्थिक, व्यापारिक दृष्टि से भारत – अमेरिकी संबंधों का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अमेरिका द्वारा एन.पी.टी व सी.टी.बी.टी पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता रखी गई। जब भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया तब अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत विदेशी सहायता, सैन्य मदद, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रमुख थे। लेकिन अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के क्रियान्वयन में गंभीरता नहीं दिखी, शायद वह भारत जैसे बड़े रक्षा व उपभोक्ता बाजार को खोना नहीं चाहता था। 1999 में भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ उस समय अमेरिका ने न केवल भारत का समर्थन किया बल्कि पाकिस्तान पर कश्मीर समस्या का हल शिमला समझौते के अंतर्गत करने का दबाव भी बनाया ।

भारत के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण में हुए परिवर्तन के स्पष्ट संकेत सन् 2000 में मिलने लगे "दि हिंदू" के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिकी – उप विदेश मंत्री ने जनवरी 2000 में यह स्वीकार किया कि मई 1998 में भारत में जो परमाणु परीक्षण और परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। टाल्बोट ने स्वीकार किया कि भारत के सुरक्षा हित मात्र

महाद्वीप तक सीमित नहीं है, अमेरिका ने यह स्वीकार कर लिया है कि अपने लिए परमाणु सुरक्षा की व्यवस्था कराना भारत का संप्रभु अधिकार है।1 मार्च 2000 में अमेरिकी – राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पांच दिवसीय भारत यात्रा को ष्एक नई शुरुआतष् की संज्ञा दी गई। जिसके परिणामस्वरूप रिश्तो में मधुरता आई। दोनों देशों ने 21वीं शताब्दी हेतु अपने दृष्टिकोण का दस्तावेज जारी किया जिसमें भारत को अमेरिका के साथ शांति सहयोग स्वतंत्रता व प्रजातंत्र का सहयोगी बताते हुए दोनों ने परस्पर ष्समान मूल्योंष् वाले ष्प्राकृतिक सहयोगीष् की संज्ञा दी जनवरी 2001 राष्ट्रपति बुश (जूनियर) ने सत्ता ग्रहण करते ही विदेश नीति में आक्रामक रूख अपनाने के संकेत दिए। अमेरिका ने घोषणा की कि दुष्ट परमाणु ताकतों से अमेरिका और उसके मित्र देशों की सुरक्षा के लिए (राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली) विकसित करना चाहते हैं, जिससे विश्व में हड़कंप मच गया।[2]

न्यूयॉर्क व वॉशिंगटन में 11 सितंबर 2001 को हवाई हमले के बाद आतंकवाद के प्रति भारत की पीड़ा अमेरिका के समझ में आ गई, तत्पश्चात दोनों देश अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक क्षेत्रीय व द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग बढ़ाने लगे दोनों देश आतंकवाद की भर्त्सना करने, उसे सबक सिखाने व भविष्य में परस्पर सहयोग हेतु सहमत हुए। अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान सैद्धांतिक रूप से तो आतंकवादियों को वैश्विक समस्या माना लेकिन व्यवहारिक रूप से उसने कोई विशेष कदम नहीं उठाए। यह तथ्य भारत में अमेरिकी राजदूत ब्लैकवेल ने स्वयं स्वीकार भी किया था। मार्च 2006 राष्ट्रपति बुश व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में हुई वार्ता में संयुक्त घोषणा की कि वे अपने द्विपक्षीय संबंधों का उपयोग भूमंडलीय भागीदारी स्थापित करने के लिए करेंगे। दोनों ही देशों की प्रतिबद्धताओं में शामिल है– मानव स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा विधि के शासन के मूल्य । भारत व अमेरिका दोनों विश्व में स्थायित्व, लोकतंत्र, संपन्नता और शांति के लिए प्रयास करते रहेंगे। दोनों देश व्यापार, पूंजी निवेश तकनीकी सहयोग के द्वारा आर्थिक विकास व सहयोग को गतिशील बनाएंगे, उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के सशक्तिकरण करने का भी निर्णय किया।[3]

इस समय अंतरराष्ट्रीय परिवेश इस प्रकार निर्मित हो रहा था जिसमें दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोग चाहिए था। जहां आर्थिक क्षेत्र में भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार व आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए अमेरिका को भारत के सहयोग की जरूरत थी वही पूंजी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा तकनीकी हस्ताक्षर करने में भारत को अमेरिका से उम्मीदें थी। सैन्य से सैन्य सहयोग एक महत्वपूर्ण पहल थी। जिसमें दोनों देश "सामरिक सहयोगी" के रुप में उभरे। जून 2005 दोनों देशों के बीच "नए भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के ढांचे" विकसित करने पर सहमति बनी। जुलाई 2005 बुश मनमोहन सिंह की घोषणा का महत्वपूर्ण मुद्दा "असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग" था। हालांकि इस घोषणा की आंतरिक व बाह्यस्तर पर बहुत आलोचना भी हुई वही समर्थन भी मिला । शंकाओ व मतमतांतर के बावजूद अगस्त 2007 में 17 अनुच्छेद, 22 पृष्ठीय, 123 समझौता लागू हो गया । इस समझौते से न केवल भारत – अमेरिकी संबंधों को मजबूती मिली, बल्कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के क्षेत्र में भी "मील का पत्थर" साबित हुई ।

नवंबर 2009 राष्ट्रपति ओबामा और मनमोहन सिंह के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिसमें वैश्विक सुरक्षा व आतंकवाद, सूचना सांझाकरण, स्वास्थ्य, आर्थिक – व्यापार कृषि व हरित सहयोग शिक्षा व विकास सम्मिलित थे। "अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकेल फ्रोमेन ने स्पष्ट किया - कि अमेरिका भारत को एन. एस.जी.की पूर्ण सदस्यता हेतु समर्थन देगा। जिससे वह MTCR, वासेनार व्यवस्था व ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में बिना NPT पर हस्ताक्षर किए जुड़ सकेगा ।[4]

नवंबर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भारत का दौरा किया। 8 नवंबर 2010 को भारतीय संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को "Defining partnership of 21st Century " कहा, भारत एशिया में उभरती एक महत्वपूर्ण शक्ति है, इस स्थिति में भारत को विश्व मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया । संयुक्त घोषणा में विश्व दो महान् लोकतंत्र के बीच गहराते संबंधों का स्वागत किया गया । दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, स्थाई व सुरक्षित दुनिया, उन्नत तकनीक, परस्पर समृद्वता को विकसित करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था की उन्नति में तीव्रता से सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी। भारत व अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी 21 वीं सदी की वैश्विक सुरक्षा व समृद्धि हेतु अपरिहार्य है"।[5] उक्त घोषणा में सैन्य संबंधों की प्रगाढ़ता पर कहा गया कि सैन्य क्षेत्र में क्रेता – विक्रेता के संबंध नहीं होकर सह –उत्पाद व सह–विकास के संबंध विकसित हुए हैं । सैन्य क्षेत्र में यह सहयोग भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण था । सितंबर 2013 में अमेरिका भारत को उन्नत परिष्कृत प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर सहमत हुआ ।

मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता ग्रहण की । सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में FDI 26% से बढ़ाकर 49% कर दी । सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने रक्षा क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की । इस अवसर पर "New Frame Work in India - US Defence Relations 2005" को नयी प्राथमिकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप नवीनीकृत किया गया । दोनों देश एक त्रिस्तरीय Indo - US - Japan के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु मंत्री स्तरीय संवाद बनाने में सहमत हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "भारत व अमेरिका के संबंध संकोच के इतिहास से उबर चुके हैं, भारत व अमेरिका एक दूसरे के साथ इतिहास व संस्कृति के माध्यम से एकनिष्ठ है।"[6]

ट्रंप प्रशासन एवं भारत – द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में वृद्धि, वैश्विक सुरक्षा, UNO के निर्णय लेने के मामलों में भारत का समावेश, NSG में प्रवेश हेतु समर्थन,

तकनीकी सांझाकरण के माध्यम से संयुक्त विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति देखी गई । साथ ही भारत और अमेरिका के बीच LEMOA समझौते पर सहमति बनी । अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया ।

1. भारत व अमेरिका के सामरिक ऊर्जा भागीदारी वर्ष (2017) घोषित किया गया ।
2. संचार संगतता और सुरक्षा समझौता(COMCASA) – 2018
3. आतंकवाद निरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्य दल की बैठक।
4. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौता।

3 अगस्त 2018 अमेरिका द्वारा भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण (STA–1) का दर्जा दिया गया। भारत–दक्षिण कोरिया और जापान के बीच तीसरा एशियाई राष्ट्र बन गया। STA–1 अमेरिका से भारत को नागरिक, अंतरिक्ष और क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात को सक्षम बनाता है। फरवरी 2020 ट्रंप की भारत यात्रा के समय ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते हुए । दोनों देशों ने आतंकवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियो को स्वीकार करते हुए इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।

जनवरी 2021 में नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता पर रखने के संकेत दिए हैं।

सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

अमेरिका भारत में सबसे बड़े प्रत्यक्ष निवेशकों में से एक है तथा दूसरा बड़ा व्यापार सहयोगी है। 2017 में 94.3 बिलियन डॉलर (भारत में आयात 25.7 बिलियन – डॉलर व निर्यात 48.6 बिलियन डॉलर) रहा वहीं 2018 में 12.6% बढ़कर कुल व्यापार 87.8 बिलीयन डॉलर हो गया। जिसमें भारत का आयात 33.5 बिलीयन डॉलर व निर्यात 54.3% रहा व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना हुआ है। भारत अमेरिका को आई. टी सेवाएं, वस्त्र, मशीनरी, रत्न व हीरे, रसायन, लौह इस्पात, कॉफी, चाय व खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है वही विमान, उर्वरक, कंप्यूटर हार्डवेयर, स्क्रैप धातु, चिकित्सा उपकरण का आयात करता है।

रक्षा सहयोग

भारत ने वर्ष 2002 में अमेरिका के साथ GSOMIA समझौता किया यह सूचनाओं के आदान–प्रदान से संबंधित है । इससे हथियारा और सैन्य संसाधनों की खरीद को बढ़ावा देना था । 2016 में (LEMOA)भारत और अमेरिका के बीच संसाधनों के आदान–प्रदान से संबंधित समझौता संपन्न हुआ । 2018 में COMCASA यानी संचार सुरक्षा समझौते पर सहमति बनी, शांति व युद्ध काल में गोपनीय संवाद बना रहेगा । हाल ही में बेसिक एक्सचेंज को – ऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर हुए रक्षा क्षेत्र दोनों देशों की यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र

हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत व अमेरिका आशियान देशों, जापान ऑस्ट्रेलिया को केंद्र में रखकर एक स्वतंत्र, खुले, समायोजित व समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा का समर्थन करते हैं । दोनों देश अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, पारदर्शी व राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के लिए सामान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं । चीन की दक्षिण चीन सागर में बढ़ती सैन्य व विस्तारवादी हरकतों का जवाब देने के लिए भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया (क्वॉड) के रूप में सहयोग बढ़ा रहे हैं तथा भारतीय नौसेना के साथ मालाबार सैन्य अभ्यास के हिस्से रहे हैं।

चीन के साथ प्रतिस्पर्धा व अमेरिका के साथ सहयोग के बीच भारत की क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका बन रही है । आज चीन वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में अपने आर्थिक व व्यापार हितों की पूर्ति हेतु सामुद्रिक संचरण मार्गों पर नियंत्रण की हर संभव कोशिश कर रहा है । वहीं भारत लुक ईस्ट व एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत द. पू. एशियाई देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है । चीन ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य विस्तारवाद से हित धारकों को भयभीत रखता ळें 2015 में भारत व अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दस्तावेज "एशिया प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र पर यू. एस. इंडिया रणनीतिक दृष्टि" पर हस्ताक्षर किए अमेरिका द्वारा घोषित नई सुरक्षा रणनीति भारत को अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक और रक्षा भागीदार के रूप में अवसर देती है ।

वैश्विक आतंकवाद

आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश सैद्धांतिक रूप से एक मत है। लेकिन अमेरिका ने आतंकवाद पर नियंत्रण पर कार्य केवल अपने राष्ट्रहित तक सीमित रखने का प्रयास किया। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर अमेरिका खुलकर निंदा करने से बचता रहा है । वह आतंकवाद की दो श्रेणियां क्षेत्रीय आतंकवाद व वैश्विक आतंकवाद परिभाषित करता है। जबकि भारत का तर्क है कि आतंकवाद के रूप के स्थान पर परिणामों पर महत्व दिया जाना चाहिए। अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सहयोग लेने के कारण नरम रुख रखता है ।

ईरान का मुद्दा

ईरान द्वारा नाभिकीय कार्यक्रम अपनाने के बाद अमेरिका व यूरोपीय संघ ने विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं । अमेरिका द्वारा भारत को भी ईरान के साथ अपने संबंध खत्म करने का दबाव दिया जाता रहा है । लेकिन ईरान के साथ भारत के सदियों पुराने ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सेंट्रल एशिया में कनेक्टविटी व अफगानिस्तान में भारतीय हितों की सुरक्षा हेतु भारत – ईरान सहयोग आवश्यक है । भारत ने अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल के आयात में कटौती की है ।

मानवाधिकार का मुद्दा

अमेरिका द्वारा कई बार कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया गया । इतिहास गवाह है कि अमेरिका केवल अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही मानवाधिकारों की पैरोंकारी करता है। उसके पिछलघ्घु

राष्ट्रों में मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर आंखें बंद कर सकता है।

द्विपक्षीय व्यापार

दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना हुआ है । कृषि उत्पादों, व्यापार सब्सिडी, कुछ उत्पादों के आयात शुल्क, बौद्धिक सम्पदा जैसे मुद्दों पर परस्पर असहमति हैं ।

भारत रूस सम्बन्ध

भारत व रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा के क्षेत्र सहयोगी रहे हैं, भारत का 60 % रक्षा सहयोग रूस के साथ है, भारत ने हाल ही में रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली – 400 प्राप्त करने का सौदा किया है । अमेरिकी कानून Countering America Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) तथा ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका का अलग होने के कारण अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का खतरा रह सकता है ।

अध्ययन का उद्देश्य

21 वीं सदी में भारत व अमेंरिका के बीच आर्थिक, व्यापारिक रक्षा, सुरक्षा, रणनीति सहयोग वैश्विक मामलों में सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

निष्कर्ष

नि:सन्देह भारत व अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों को वैश्विक रणनीतिक साझेदारी कहा जा सकता है। आज विश्व के दो सर्वाधिक सशक्त लोकतांत्रिक राज्य आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की दृष्टि में एशिया महाद्वीप में चीन की ताकत को संतुलित करने के लिए भारत का सशक्त होना अनिवार्य है क्योंकि चीन सैन्य व आर्थिक रूप से अमेरिका के लिए चुनौती के रूप में उभरा है। चीन की बीआरआई परियोजना, सामुद्रिक संचरण मार्गों पर नियंत्रण, दक्षिणी एशिया में सैन्य व्यापार, आर्थिक निवेश, दक्षिण चीन सागर में सैन्य विस्तारवाद, व्यापार घाटा, हांगकांग, ताईवान, तिब्बत के मुद्दे अमेरिका के लिए चुनौती है । ईरान – चीन– रूस की धुरी क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति को प्रभावित करेगी इस स्थिति में अमेरिका के लिए भारत के साथ संबंधों की उपादेयता बढ़ रही है। शीत युद्ध के बाद बदले परिवेश में अमेरिका की दृष्टि में पाकिस्तान का उतना महत्व नहीं रह गया है। भारत का वृहद उपभोक्ता व रक्षा बाजार अमेरिका को आकर्षित करता है । शीत युद्ध समाप्ति के बाद बढ़ते भारत अमेरिकी संबंधों के कारण रूस के साथ संबंधों में ऊष्णता नहीं रही है । हमें सचेत रहना चाहिए कि रुस हमारा परिक्षित मित्र व सहयोगी रहा है रूस के चीन व पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए भू– राजनीतिक व भू– रणनीतिक रूप से चुनौती हो सकती है। अतः भारत को अमेरिका व रूस के साथ संबंधों में संतुलनकारी भूमिका तलाशनी होगी । हमें पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने व आतंकवाद का गर्भगृह घोषित कराने में अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए। जहाँ तक चीन का संबंध है भारत व अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ अंतर्निहित हैं। चीन दोनों देशों का प्रमुख व्यापार सहयोगी है। भारत चीन का पड़ोसी राष्ट्र है। दोनों की सैन्य व आर्थिक क्षमता में भी अंतर है व्यापार संबंधों में चीन को बायकॉट करने के स्थान पर वैश्विक शक्तियो के साथ मिलकर उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, हमें चीन पर व्यापार निर्भरता कम करनी होगी। चीन इंडो पेसिफिक क्षेत्र में क्वॉड की भूमिका को अपने विरुद्ध सैन्य व आर्थिक धुरी के रूप में देखता है । भारत को क्वॉड में अपनी भूमिका के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को भी बनाए रखना होगा । यह भारतीय रणनीतिकारों व राजनयिको के समक्ष चुनौती होगी कि भारत किस प्रकार महाशक्तियों के बीच संतुलनकारी भूमिका में रहे ।

निश्चित रूप से भारत – अमेरिका की आर्थिक – सामरिक सांझेदारी न केवल दोनों देशों के लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराएगी वरन् विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों व मानवीय हितों की सुरक्षा का बेहतर प्रयास होगा । वैश्विक शांति, सहयोग, समृद्धि, विकास में प्रगति के लिए दोनों महान राष्ट्रों के बीच साझेदारी वैश्विक मांग है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *वी. एन. खन्ना व लिपाक्षी अरोड़ा, "भारत की विदेश नीति" विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. नोएडा (यू. पी.) 2015 पृष्ठ 367*
2. *बी. एल. फुड़िया, "अंतरराष्ट्रीय राजनीति" सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे "साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2011पृष्ठ 193.*
3. *बी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, वही पृष्ठ 369*
4. *The Indian Express] Nov 9, 2010.*
5. *The Hindu] Nov 9, 2010.*
6. *डॉक्टर सारिका दुबे, "मोदी की विदेश नीति के चार साल": "महाशक्तियों व पड़ोसी देशों के संदर्भ में" वर्ल्ड फोकस अंक जनवरी 2019 पृष्ठ 78*